06/09/1988 'हिन्दुस्तान' (ok) [illegible] 'हिन्दुस्तान' (नयी दिल्ली, पटना) 06/09/1988

बर्मा में अब समाजवादी फतवा नहीं चलेगा

□ शशिधर खां

गत १९ अगस्त को ६३ वर्षीय मागमाग को बर्मा की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी (बी.एस.पी.पी.) ने राष्ट्रपति और पार्टी अध्यक्ष चुन लिया। जैसी कि संभावना थी, मांगमांग का भी जनता ठीक उसी तरह विरोध कर रही है जिसको वजह से १२ अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति सेन ह्लिन को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। क्योंकि मांगमांग भी जनरल ने विन के उतने ही नजदीकी व्यक्ति माने जाते हैं, जितने सेन ह्लिन। श्री मांगमांग जनरल ने विन के कानूनी सलाहकार थे और सेनलिन ने २३ जुलाई को उन्हें देश का अटॉर्नी जनरल बनाया था।

दरअसल वर्षों की सताई और क्रूर तानाशाही की चक्की में पिसी बर्मा की जनता ने विन की छाया तक नहीं देखना चाहती। अपने २६ वर्षों के प्रशासन में समाजवाद का फतवा देकर देश की जनता के नागरिक अधिकारों का दमन करके जनरल ने विन ने पूरे देश को तहस-नहस करके रख दिया। बर्मा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई और नैतिकता तथा सिद्धान्तों की बलि चढ़ा दी गई।

मार्च, १९६२ में ने विन ने एक रक्तहीन क्रांति में बर्मा की सत्ता अपने हाथ में ली। उस समय न्यू बर्मा के प्रधानमन्त्री थे, जिन्हें ने विन ने सत्ता से हटाया। चार जनवरी, १९४८ को बर्मा को आजादी मिली मगर कारेन, शान, काचीन, मोन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए और देश नये संकट में फंस गया। तत्कालीन प्रधानमन्त्री न्यू ने दंगों पर काबू पाने के लिए ने विन को पूरी छूट दे दी। कहर ढाने के लिए अंग्रेजों द्वारा ?80 का पदक प्राप्त सेना के सर्वोच्च कमांडर ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे जोरदार आन्दोलन कम्युनिस्टों का था जिसका वे पूरी कोशिश के बावजूद सफाया नहीं कर सके। हां, आन्दोलन थोड़े समय के लिए दब भर जरूर गया।

सन् १९६० के चुनाव में प्रधानमन्त्री यू न्यू का पुनः सत्ता में आना महात्वाकांक्षी ने विन को अखर गया। यों भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापारियों का दबदबा उन्हें पसंद नहीं था।

ने विन की क्रांतिकारी सरकार

आखिर १९६२ में यू न्यू को बलपूर्वक सत्ता से हटाकर ने विन स्वयं सर्वेसर्वा बन गए। सेना पर तो इनका पूर्ण नियन्त्रण था ही, जनता भी पूरी तरह से साथ थी, क्योंकि देश को अंग्रेजों के औपनिवेशिक गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए ने विन ने कठिन संघर्ष किया। उन्होंने इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया।

ने विन ने क्रान्तिकारी सरकार बना कर आते ही बड़ी अजीबोगरीब व्यवस्था की नींव डाली। कम्युनिस्टों की हैसियत का उन्हें बखूबी अंदाजा था, शायद इसीलिए बौद्ध धर्म की राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता खत्म कर दी। एक विचित्र ढंग का समाजवादी फतवा देकर उसे 'बर्मी समाजवाद' नाम दिया और उसकी आड़ में ने विन ने सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वे सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जो एक सैनिक तानाशाह अपनाता है।

अपने पूर्व प्रधानमन्त्री को हटाने का कारण उन्होंने यह बताया कि बहुदलीय जनतंत्रीय शासन प्रणाली से देश की वर्तमान समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी तथा साम्प्रदायिक तत्वों को भी बढ़ावा मिलेगा।

एक धूर्त और कुशल नेता ने विन निरंकुश शासन में बने रहने के सारे गुणों से पारंगत थे। न तो उन्हें बुद्ध से कुछ लेना देना था न ही कार्ल मार्क्स से। लोकिन ने विन ने दोनों की दुहाई दी और जनता की भावनाओं से जी भरकर खिलवाड़ किया। क्योंकि बर्मा में बौद्धों और कम्युनिस्टों को मिलाकर ही उन्हें अपनी तानाशाही की नींव मजबूत करनी थी। उनका समाजवाद न तो रूसी था न ही चीन का।

ने विन ने मनुष्य के अपने आसपास के वातावरण से अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने का सिद्धान्त दिया। ये सिद्धान्त स्कूलों में पढ़ाए गए, मगर कभी इस पर बिस्तार से चर्चा नहीं की गई ताकि इसका वास्तविक तात्पर्य स्पष्ट हो सके। नैतिकता का कड़ाई से पालन कराने का दंभ भरने वाले ने विन ने स्वयं चार शादियां की।

विचित्र आर्थिक नीति

आर्थिक मामलों में भी ने विन ने विचित्र नीतियां अपनाई। व्यावसायिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र से सम्बद्ध सभी विदेशी व्यापारियों को बर्मा छोड़ देने का आदेश दिया। उनमें अधिकांश व्यापारी चीन और भारत के थे। आर्थिक राष्ट्रीयकरण का तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि देश के पचहत्तर फीसदी बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बन्द होने की नौबत आ गई, क्योंकि उनमें मुख्य रूप से विदेशी पूंजी लगी थी। ने विन ने व्यापार करने के उद्देश्य से विदेशियों के आने पर रोक लगा दी। इससे बर्मा विश्व के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया और कई एशियाई देश विला वजह इसके दुश्मन बन गए

बर्मा की जनता अब पूरी व्यवस्था बदलने पर आमादा है, इसलिए मांगमांग की भी कोई नीति उन्हें रास नहीं आ सकती। उन्होंने अधिक जनतंत्रीय और उदारवादी रुख अपनाने के आश्वासन दिए हैं, मगर जनता 'नकली' नहीं, 'असली' समाजवाद चाहती है और जब तक यह कायम नहीं हो जाता बर्मा में अशांति और अव्यवस्था बनी रहेगी।

फिर तो बड़े पैमाने पर चोरबाजारी होने लगी। बर्मा की आय के मुख्य स्रोत मजबूत लकड़ी और कीमती पत्थर चोरी छिपे थाइलैंड और मलेसिया के रास्ते बाहर जाने लगे। कई एशियाई देशों को ने विन की राजनीतिक नीतियों से भी नाराजगी थी, इसलिए भी वे बर्मा के पीछे पड़ गए। बर्मा की सीमाओं पर विद्रोही गतिविधियां तेज हो गई और भारी संख्या में उन विद्रोहियों को विदेशी हथियार मिलने लगे। उपद्रवों की वजह से सरकारी खर्चा बढ़ा। किसानों पर नये कर लगाए गए, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कृषि पर पहले भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया था। सारा दक्षिणपूर्व एशिया ने विन के पीछे पड़ गया। इतना सब होने के बावजूद ने विन की सत्ता पर पकड़ ढीली नहीं पड़ी, क्योंकि सेना पूरी तरह उनके साथ थी और जनता मजबूर थी। ने विन की नजर में विरोधियों का इलाज था बिना मुकदमा के सजाए मौत।

इस ऊहापोह में दस वर्ष बीत गए और १९७२ में ने विन ने सरकारी तौर पर सेना से अवकाश ग्रहण किया। दो वर्ष में उन्होंने देश का नया संविधान बनाया और १९७४ में राष्ट्रपति बन गए, जो पद नवम्बर १९८१ में दिखावे के लिए त्याग दिया। हालांकि स्वनिर्मित बी. एस. पी. पी. (बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी) पर ने विन का नियंत्रण पूर्ववत था मगर जनता उनसे खार खा चुकी थी और १९७२ से ही जो थोड़ी-थोड़ी मुगबुगाहटें शुरू हुई वो १९८१ आते-आते प्रकट हो गयी। बौद्ध-भिक्षु और कम्युनिस्ट भी ने विन से तंग आ चुके थे, जनसाधारण का जीना दूभर हो गया था और देश के तमाम बुद्धिजीवियों की राष्ट्रपति को समझने की सारी कोशिशें बेकार हो गयी थीं। उसी समय वे गुप्त सभाएं और मंत्रणाएं लगीं। ने विन की विदूप दमनकारी नीति के चलते खुले में यह सब संभव नहीं था।

बर्मी नागाओं को प्रोत्साहन

पहले भारत बर्मा की गतिविधियों से बेखर था मगर १९७२ से मुक्तातिब होना जरूरी हो गया जब ने विन ने नागालैंड से सटी सीमा पर स्थित बर्मी नागाओं को उकसाया और उस क्षेत्र के विद्रोहियों को हथियार देना शुरू कर दिया। ने विन ने उन विद्रोहियों को न केवल अपने यहां शरण दी बल्कि बर्मा के रास्ते चीन निर्मित हथियार जुटाने में भी मदद पहुंचायी। इस तरफ ध्यान देने का प्रतिकूल असर पड़ा और बर्मा की जनता को संगठित रूप में विरोधी योजनाएं बनाने में सहूलियत हुई। हालांकि ने विन इस तरफ से भी सतर्क थे।

अब तक सेना ने विन के साथ थी, इसलिए उन्हें किसी की परवाह न थी। १९८० के बाद सेना का उनकी ओर से मोहभंग होने लगा और सैनिकों में जनता के खिलाफ हथियार उठाने में आनाकानी की प्रवृत्ति देखी गयी।

पिछले दो वर्षों से अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों से ७७ वर्षीय ने विन को लग गया था कि अब वे सत्ता में बने नहीं रह पायेंगे। इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही रोजाना उनके विरुद्ध छात्रों, बौद्ध-भिक्षुओं और समाज के विभिन्न वर्गों की नारेबाजी होने लगी। हार कर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ का बहाना करके २३ जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और अपने अति विश्वसनीय व्यक्ति ६४ वर्षीय भूतपूर्व ब्रिगेडियर सेन ह्लिन को सत्ता सौंप दी।

मगर २६ वर्षों से ने विन को झेल रही बर्मा की जनता सेन ह्लिन को एक दिन भी बर्दाश्त करने को तैयार न थी। इसलिए जिस दिन सेन ह्लिन ने राष्ट्रपति और बर्मी सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी को अध्यक्ष पद संभाला, उसी दिन से उनके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन और आन्दोलन शुरू हो गया। इस बार का आन्दोलन ने विन के जमाने जैसा नहीं था। पहले से ज्यादा व्यापक और उग्र था। प्रदर्शन में शामिल छात्र और बौद्ध भिक्षु मरने-मारने पर उतारू थे और सबसे बड़ी बात यह कि सेना ने खुलेआम उनका साथ दिया। एक प्रकार से सेन ह्लिन के खिलाफ यह खुला विद्रोह था, जिसे दबाना सेन ह्लिन के वश से बाहर थी। कई जगह सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से साफ इंकार कर दिया।

एक सप्ताह में दो हजार की हत्या

हालांकि सेल ह्लिन ने अपनी ओर से विद्रोह की कुचलने की भरपूर कोशिश की। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने दो हजार के लगभग लोगों की मरवा दिया और अपने विश्वस्त सैनिक कमांडरों को कहर मचाने का पूरा अधिकार दे दिया। इतना करने के बावजूद वे आन्दोलन की आग कम नहीं कर सके, बल्कि उल्टे आन्दोलन और जोर पकड़ने लगा। बर्मा की तीन करोड़ आठ लाख आबादी में इतना जोश और उत्साह पहली बार देखा गया।

बैंकाक के माध्यम से संसार को बर्मा की अंदरूनी गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। बौखलाहट में आकर सेन ह्लिन ने थाइलैंड को बर्मा से लगी सीमा सील कर दी और उस मार्ग से आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा दी।

लेकिन वे सारे हथकंडे नाकामयाब साबित हुए और १२ (बारह) अगस्त को सेनलिन को राष्ट्रपति और अध्यक्ष पद के साथ-साथ देश भी छोड़ना पड़ा। बात सिर्फ उन्हीं के हट जाने से समाप्त हो जाती, अगर नये राष्ट्रपति का ने विन से पहले कोई लगाव न रहा होता।

मामला ने विन या सेन ह्लिन के जाने और मांगमांग के आने का नहीं है। पार्टी वही है, उसके सारे अधिकारी ने विन के लाये हुए हैं और उन्हीं के द्वारा कायम की गई व्यवस्था बरकरार है। ने विन की पार्टी में मांगमांग अकेले व्यक्ति थे, जिनका सेना से कोई तात्लुक नहीं था। वे अपेक्षाकृत नरम और उदार प्रवृत्ति के हिमायती माने जाते हैं। उन्होंने लंदन और वाशिंगटन में कानून की पढ़ाई की है।

ताजातरीन सूचनाओं के अनुसार वर्तमान शासन-व्यवस्था का व्यापक जन विरोध होते देखकर ने विन ने अपने देश में टिके रहना खतरनाक समझा और २४ अगस्त को निकल भागे। उन्होंने कई यूरोपीय देशों से राजनीतिक शरण मांगी थी, मगर किसी भी देश ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दें भी कैसे, सत्ता के मद में चूर ने विन ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के साथ-साथ राष्ट्रमंडल देशों से भी तो बर्मा को अगल-थलग कर दिया था। अब सेन ह्लिन भी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कहीं जुगाड़ बिठाने की फिराक में हैं।

पिछले दिनों करीब दस लाख लोगों ने बर्मा के विभिन्न शहरों में उग्र प्रदर्शन करके जतला दिया कि यह निरंकुश एकदलीय शासन-प्रणाली अब कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बर्मा में इतना विशाल प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। जर्रे-जर्रे से लोकतंत्र की आवाजें उठ रही हैं। संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी शुरू है।

सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी ने उदारवादी विचारधारा का हिमायती होने के कारण ही मांगमांग को राष्ट्रपति बनाया था, ताकि इससे जनता शांत हो जाएगी। लेकिन दिन प्रतिदिन विरोध उग्रतर होते देख मांगमांग को अपना उदारवाद दांव पर लगाना पड़ा। अब वे भी बखूबी समझ गए हैं कि यह गाड़ी चलनेवाली नहीं है।

और कोई चारा न देख २३ अगस्त को शाम में मांगमांग ने रंगून रेडियो पर 'मार्शल लॉ' हटाने की घोषणा की और भूतपूर्व ब्रिगेडियर तथा लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक आंग गई को रिहा कर दिया। सेन ह्लिन ने राष्ट्रपति बनने के दूसरे ही दिन विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल ला लागू कर दिया था और औंगगई को नजरबंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ने विन को पत्र लिखकर कुछ नागरिक अधिकार देने का आग्रह किया था।

मांगमांग ने १२ सितम्बर को पार्टी कांग्रेस की आपात बैठक बुलायी है। उसी दिन जनमत संग्रह कराया जाएगा। राष्ट्रपति की घोषणा के मुताबिक अगर जनमत उनके खिलाफ गया तो वे अपनी सरकार के सभी अधिकारी समेत इस्तीफा दे देंगे।

मगर जनता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जनता की मांग है कि मांगमांग तुरत इस्तीफा दें, एक अंतरिम सरकार बने और संविधान में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया जाए ताकि जनतांत्रिक तरीके से चुनाव हो सके। बर्मा के सभी अखबारों के कर्मचारियों ने भी इसके समर्थन में हड़ताल कर दी है।